बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 196 ● नई दिल्ली ● वीरवार 21 मई 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

दिल्ली सरकार की लॉन्च की सपनों की उड़ान, 'दिल्ली टैलेंट हंट में 25 हजार युवाओं की प्रतिभा को मिलेगा मंच

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने युवाओं की छिपी प्रतिभाओं को सामने लाने के उद्देश्य से 'दिल्ली टैलेंट हंट योजना' शुरू की है। इस योजना को 'सपनों की उड़ान' नाम दिया गया है। योजना के तहत राजधानी के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। योजना के शुभारंभ के दौरान रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है ताकि दिल्ली के युवा अपनी क्षमता, रचनात्मकता और मेहनत के दम पर नई पहचान बना सकें। सरकार के अनुसार इस योजना में करीब 25 हजार युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रतिभागियों को गायन, नृत्य, रंगमंच, ललित कला, डिजिटल कला, वाद्य संगीत और संगीत रचना जैसे क्षेत्रों में मंच उपलब्ध कराया जाएगा।

-: भारत की छवि पर वार : -

नॉर्वे के अखबार में छपा पीएम मोदी का 'अपमानजनक' कार्टून

नई दिल्ली । नॉर्वे के प्रमुख अखबार आफ्टेनपोस्टेन द्वारा प्रकाशित एक कार्टून को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इस कार्टून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्नेक चार्मर यानी सपेरा दिखाया गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इसे नस्लवादी और अपमानजनक बताया जाने लगा। कार्टून में मोदी को पारंपरिक 'पुंगी' बजाते हुए दिखाया गया था, जबकि सामने पेट्रोल पंप की नोजल के आकार का सांप नजर आ रहा था। इसे हालिया पेट्रोल-डीजल कीमतों के संदर्भ से जोड़ा गया। यह चित्र एक राय लेख के साथ प्रकाशित हुआ, जिसका अनुवादित शीर्षक था एक चतुर और थोड़ा परेशान करने वाला व्यक्ति। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई लोगों ने इस कार्टून की आलोचना करते हुए कहा कि यह भारत और भारतीयों के खिलाफ पुरानी औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाता है। कुछ यूजर्स ने कहा कि दुनिया अब भी भारत को सपेरों का देश दिखाने की कोशिश कर रही है, जबकि भारत आज तकनीक और डिजिटल क्षेत्र में बड़ी ताकत बन चुका है।

केरल में सतीशन सुपर बॉस, अपने पास रखे 35 विभाग, चेन्निथला बने होम मिनिस्टर

केरल। केरल सरकार ने नए मंत्रिमंडल में विभागों के आवंटन की घोषणा की. केरल लोक भवन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने वित्त, कानून, सामान्य प्रशासन और पोर्ट सहित 35 विभागों का प्रभार अपने पास रखा है. मुख्य फैसले लेने और नीतियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण विभाग खुद मुख्यमंत्री संभालेंगे, जिसका मतलब ये है कि सरकार चलाने की वास्तविक मुख्य शक्तियां मुख्यमंत्री कार्यालय के पास ही रहेंगी. कांग्रेस के सीनियर नेता रमेश चेन्निथला को गृह मंत्रालय और विजिलेंस विभाग सौंपा गया है. विजिलेंस भ्रष्टाचार पर नजर रखने वाला विभाग होता है. इसके अलावा वे तीन और विभागों का कामकाज भी संभालेंगे. IUML के पौंके कुन्हालीकुट्टी उद्योगों और बिजनेस से जुड़े 7 विभाग संभालेंगे, जिनमें उद्योग, आईटी और कपड़ा मंत्रालय शामिल है. केरल कांग्रेस अध्यक्ष सनी जोसेफ को बिजली और पर्यावरण मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है. के. मुरलीधरन को स्वास्थ्य, देवास्वम (मंदिरों और धार्मिक स्थलों की देखरेख करने वाला विभाग) मंत्री बनाया गया है. केरल सरकार में रेजी एम. जॉन उच्च शिक्षा विभाग संभालेंगे, जबकि ए. पी. अनिल कुमार को भूमि एवं राजस्व विभाग मिलेगा. शम्सुद्दीन को केरल का नया सामान्य शिक्षा मंत्री बनाया गया. केरल के मुख्यमंत्री वी डी सतीशन ने बुधवार (20 मई 2026) को कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा के धर्मनिरपेक्ष रुख पर कोई समझौता नहीं होगा. उन्होंने यह भी कहा कि यूडीएफ सांप्रदायिकता का कड़ा विरोध करेगा. मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सीएम सतीशन ने कहा कि उनके और यूडीएफ द्वारा अपनाए गये धर्मनिरपेक्ष रुख में कोई बदलाव नहीं आया है.

पश्चिम बंगाल की सरकार राष्ट्रवादियों की होगी- मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी

बंगाल।पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार को कहा कि पश्चिम बंगाल की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार राष्ट्रवादियों की होगी और वह भारतीय परंपरा और संस्कृति को कायम रखेगी। शुभेंदु ने कहा कि नवगठित भाजपा सरकार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान घोषणापत्र में किए गए सभी वादों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करेगी। मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने पहले दौरे पर उत्तर बंगाल पहुंचने पर भाजपा कार्यालय में अपने संबोधन में अधिकारी ने कहा कि भाजपा ने अपने संकल्प पत्र (चुनाव घोषणापत्र) में जो घोषणाएं की थी उनका लाभ लोगों को मिलना शुरू हो गया है। नयी सरकार ने अन्नपूर्णा योजना शुरू करने का फैसला किया है, जिसके तहत ममता बनर्जी सरकार की लक्ष्मीर भंडार योजना में महिलाओं को दी जाने वाली 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता को दोगुना करके 3,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। सरकार ने महिलाओं के लिए सरकारी बसों में यात्रा निःशुल्क कर दी है और राय में आयुष्मान भारत योजना शुरू करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारी सरकार जनता की आकांक्षाओं को पूरा करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, हम सिर्फ सत्ताधारी दल के झंडे का रंग या शीर्ष पर बैठे लोगों को बदलना नहीं चाहते बल्कि हम व्यवस्था में बदलाव चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बदले हुए हालात में पश्चिम बंगाल में न तो गिरोह चलेंगे, न ही रिश्वतखोरी का चलन रहेगा, न माफिया राज रहेगा और न ही किसी तरह की राष्ट्रविरोधी गतिविधि होगी।

भीषण गर्मी -25 मई तक घर में ही रहें

दिल्ली-एनसीआर में आईएमडी ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट; 45 डिग्री तक पहुंचेगा तापमान

नई दिल्ली। दिल्ली में गर्मी लगातार जोर पकड़ रही है। इस पूरे सप्ताह ही दिल्ली वासियों को भीषण गर्मी का सामना करना होगा। तीखी धूप में तापमान में भी तेजी से वृद्धि होगी और अगले लू भी चलेगी। मौसम विभाग ने 25 मई तक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। दूसरी तरफ दिल्ली की वायु गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में ही चल रही है। बुधवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 28.3 डिग्री दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 45 डिग्री के आसपास रह सकता है। दिन भर आसमान साफ रहेगा एवं तेज धूप भी निकली रहेगी। गर्म हवा के थपेड़े भी खाने पड़ सकते हैं। उधर बुधवार को सुबह नौ बजे दिल्ली का एक्यूआइ 187 दर्ज किया गया। इसे मध्यम श्रेणी में रखा जाता है। एनसीआर के शहरों में भी हवा मध्यम से खराब श्रेणी में ही चल रही है। पूर्वानुमान है कि जल्द फिलहाल इसमें बहुत अधिक बदलाव नहीं होगा।

बीजेपी सरकार कर रही आरक्षण की लूट- अखिलेश यादव

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को भाजपा सरकार पर आरक्षण व्यवस्था को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि संविधान के तहत प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करने के लिए लोगों को अदालतों का रुख करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए यादव ने आरक्षण की लूट पर पीडीए ऑडिट नामक एक दस्तावेज जारी किया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पीडीए ऑडिट और आरक्षण की लूट पर यह दस्तावेज लगातार बेहतर होता रहेगा और इसमें और अधिक आंकड़े शामिल किए जाएंगे। यादव ने जून 2023 में पीडीए शब्द गढ़ा था, जिसका अर्थ है पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक। उन्होंने कहा कि वर्चस्ववादी ताकतें रोजगार बाजार में आरक्षण को खत्म कर रही हैं। वे एनएफएस (उपयुक्त नहीं पाया गया) का भ्रामक नारा फैला रही हैं और अपने जैसी विचारधारा वाले लोगों को पिछले दरवाजे से नौकरी दिलवाने में लगी हैं। भाजपा छल कर रही है। भाजपा असमानता के खिलाफ सदियों पुरानी इस लड़ाई को अनुचित तरीकों से जीतना चाहती है। वह तीसरे पक्ष - न्यायपालिका - को भी प्रभावित करने की हद तक जा रही है। उन्हें समानता नहीं चाहिए। सत्ताधारी भाजपा को निशाना बनाते हुए यादव ने कहा कि अगर छात्रों और उम्मीदवारों को संवैधानिक प्रावधानों को लागू करवाने के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाना पड़े, तो यह समझा जाना चाहिए कि सरकार पक्षपातपूर्ण है। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर हमें संवैधानिक अधिकारों के लिए अदालतों का रुख करना पड़े, तो इसका मतलब है कि सरकार पक्षपातपूर्ण है। और जो पक्षपातपूर्ण होता है, वह विश्वासघाती भी होता है। पक्षपात अपने आप में अन्याय है क्योंकि यह अधिकारों को छीन लेता है। संसद प्रमुख ने आरक्षण को सामाजिक न्याय और समानता का साधन बताया। उन्होंने कहा कि आरक्षण सुरक्षा है। आरक्षण सामाजिक समन्वय का एक उपकरण और माध्यम भी है। भाजपा सरकार की मनमानी कार्रवाई का जिक्र करते हुए यादव ने कहा कि अगर भाजपा सरकार को बुलडोजर का इस्तेमाल करना ही है, तो उन्हें असमानता की खाई को पाटने और सभी को उनका उचित आरक्षण दिलाने के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहिए।

ट्रक से टकराई तेज रफ्तार कार, 4 छात्रों की मौत, 2 गंभीर

अमरोहा।

उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। राष्ट्रीय राजमार्ग-9 पर आज सुबह तड़के एक वैगनआर कार और ट्रक के बीच हुई भीषण टक्कर में चार युवकों की मौत हो गई जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में तीन युवक पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे जो वाराणसी के एक मदरसे में पढ़ाई करते थे। यह हादसा गजरौला थाना क्षेत्र के खालीपुर ढाल स्थित नयारा पेट्रोल पंप के पास सुबह करीब चार बजे हुआ। पुलिस के अनुसार टक्कर इतनी भीषण थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।

थाली बजवाना भूल न जाना!

देवतुल्य मोदी जी को एक पक्के भक्त का दंडवत प्रणाम पहुंचे! अपने परिवार में अपने मुंह से क्या कहूं। बस इतना समझ लीजिए कि आपने जो विदेश यात्रा पर निकलते-निकलते पेट्रोल-डीजल-सीएनजी के दाम तीन-तीन रुपया बढ़ाए हैं, उस पर कोई आपके खिलाफ कुछ कहता है, तो वह कौन है मैं नहीं देखता, सीधे उससे भिड़ जाता हूं। कम से कम दस रुपये बढ़ने को राहत में एकदम जल्दी बताता हूं। आखिर में मुकाबले से वह कहे बिना पलटकर नहीं आता हूं कि पेट्रोल चाहे चार सौ रुपये पर चला जाए, हम मोदी पर मोदी जी को ही बैठाएंगे-- बार-बार, हर बार, लगातार! आज जब आप वहां गोदी के देशों में जाकर भी भारतीयों को ही भारत के बारे में बता रहे हैं, भारतीयों के ही नाच-गानों के साथ भारतीयों से ही अपना स्वागत करा रहे हैं और होके तस्वीर में होके ऐंगल से इतने खुश नजर आ रहे हैं, आपका मजा किरकिरा करने के लिए आपको यह चिट्ठी लिखने का सच पूछिए तो मेरा जरा सा भी मन नहीं था। पर आप जो जाते-जाते देश को त्याग का इतना महान संदेश देकर गए हैं, आपके विरोधियों के उसकी हंसी उड़ाने पर मुंह सिलकर भी तो नहीं बैठा सकता था। वैसे तो आप सर्वज्ञाता हैं, फिर भी सोचा आप के संज्ञान में ला दूं कि आपके विरोधी यानी राष्ट्र विरोधी, आपके उपदेश का कैसे मजाक उड़ा रहे हैं? इसे त्याग की महत्ता का बोध नहीं, देश को संकट में गंभीर संकट में फंसा देने का कबूलनामा बता रहे हैं। यूरोप की ठंडी हवाओं से भारत की झुलसाने वाली गर्मी में वापस आएंगे, तो आपको इन विरोधियों के मुंह बंद कराने वाले जवाब तैयार करने आना होगा, बस यही सोचकर यह भक्त आपके रंग में भंग करने की जुर्रत कर रहा है। आप जो ने भारतवासियों से कितनी अच्छी बात कही है। अच्छी क्या एकदम संस्कारी बात कही है। भारतीय संस्कृति और धर्म में रची-बसी बात कही है। संस्कारों में ऊंची, पर करने में एकदम आसान बात कही है। पब्लिक से सादगी का जीवन जीने की बात कही है। विराट संकट का सामना करना है, फिर भी पब्लिक से एकदम छोटे-छोटे त्याग करने की बात कही है। जलाने का तेल, कम से कम जलाओ; न मोटर, न मोटरसाइकिल, न साइकिल पर आओ-जाओ। खाने का तेल भी कम से कम खाओ। खुद तो कम खाओ ही, अपने साथ-साथ खेतों को भी कम खाद खिलाओ। विदेशी चीजें मत खरीदो। विदेशी मुद्रा बनाओ। कुछ भी बढ़ाना हो एक साल सोना मत खरीदो। एक साल सैर-सपाटे पर विदेश मत जाओ। बताइए इतने छोटे-छोटे त्याग। और यह भी पब्लिक को ही स्वास्थ्य लाभ समेत कई-कई लाभ पहुंचाने वाले त्याग मांगे हैं। बाकी तो छोड़ ही दीजिए, लाल बहादुर शास्त्री की तरह, हफ्ते में एक वक्त के खाने का त्याग तक नहीं मांगा। और तो और अस्सी करोड़ से राशन का त्याग तक नहीं मांगा। चीनी का त्याग नहीं मांगा। मसाले-वसाले का त्याग भी नहीं मांगा। रसोई में से मांगा भी तो सिर्फ खाने के तेल का त्याग और बेशक, पकाने की गैस का त्याग। विरोधियों को इसी में त्याग पर हल्ला करनी चाहिए क्या? पर हल्ला कर रहे हैं। कह रहे हैं ये कि ये त्याग के उपदेश तो सिर्फ पब्लिक के लिए हैं, खुद ये सब त्याग के दिखाएं तो जानें। ये तो पर उपदेश कुशल बहुतेरे का मामला है। लेकिन, आप जी का आदेश मानकर, भगवा पार्टी के नेतागण बेचारे जरा सी सादगी अपना भी रहे हैं, तो इसमें भी विपक्षी मीन-मेख निकालने लगे। पहले मंत्रियों से लेकर संतरियों तक, हमारे नेता दर्जनों गाड़ियों के काफिले में चलते थे, तब इन्हें प्राब्लम थी कि काफिले में क्यों चलते हैं? पब्लिक को हर वक्त अपना राजा-पन क्यों दिखाते हैं? और जो और विरोधियों ने तो आपके त्याग के उपदेश के अगले दिन से ही इसके ताने भी देने शुरू कर दिए थे कि मोदी जी पब्लिक से तो तेल बचाने की मांग कर रहे हैं और खुद उनकी पार्टी और राज के छोटे-छोटे प्यादे तक, खामखां में दर्जनों गाड़ियों में तेल फूंक रहे हैं। और अब, जब आपके भक्तगण सादगी अपना रहे हैं, कोई बस से, तो कोई मेट्रो से, तो कोई मोटर साइकिल से तो कोई टुकटुक से और कोई-कोई तो साइकिल तक से इधर-उधर जाते सोशल मीडिया पर नजर आ रहे हैं, तो विरोधी उसमें भी खोट निकाल रहे हैं। देखना तो चाहिए यह कि सत्ता कुल के लोग काफिले से दूर, अकेले बस, मेट्रो, मोटर साइकिल वगैरह से आ-जा रहे हैं, पर वह न देखकर अपनी नकारात्मकता में ये सिर्फ यह देख रहे हैं कि इनमें से हरेक की सवारी के आगे-पीछे, गाड़ियों का काफिला तो ज्यों का त्यों चल रहा है; तेल तो पहले से भी ज्यादा जल रहा है! सत्ता कुल के त्याग से प्रेरणा लेकर खुद भी तेल बचाने के बजाए, कह रहे हैं कि यह तो सिर्फ दिखावा है। यह सादगी रीयल तेल बचाने के लिए नहीं, तेल बचाने की रील बनाने के लिए है! शुक्र है कि आप जी के भक्त भी आप की ही तरह इन विपक्षियों की बातों की परवाह नहीं करते हैं। और क्यों करें? उनके भगवान का संदेश, काफिले तस्वीर से बाहर करने का है और सो वे बखूबी कर रहे हैं। अपनी सादगी को जम कर वायरल भी कर रहे हैं। रही विपक्षियों की बात, तो ये तो उनके भगवान में भी खोट निकालते हैं। आप जी ने अपने चुनावी शो, रोड शो, हवाई शो वगैरह से फुर्सत मिलते ही, विदेश यात्रा पर निकलने से पहले ही, एक अपनी, एक सुरक्षा की, एक कैमरे वालों की, कुल तीन गाड़ियों के काफिले में लुटियन की दिल्ली में घूमने का वीडियो बनाकर भी दिखा दिया, फिर भी विरोधियों को आपकी सादगी और तेल की कमखर्ची दिखाई ही नहीं। उल्टे आप जी की विदेश यात्रा पर ही सवाल उठाने लग गए; एक साल विदेश यात्रा न करने का त्याग क्या दूसरों के लिए ही है? बहुत अच्छा है कि इन विरोधियों की न आप जी परवाह करते हैं और न आपके भक्त! ये विरोधी हैं ही इसी लायक। ये भारतीय संस्कृति और संस्कारों को न जानते हैं और न मानते हैं बल्कि जान-बूझकर उनका तिरस्कार करते हैं, हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए। वर्ना जब हाथ की पांच उंगलियां भी बराबर नहीं होतीं, तो राजा और प्रजा कैसे बराबर हो जाएंगे? प्रजा वाली बंदिशें राजा पर कौन लगाता है, जी! और हां, आप जी ने यह बहुत अच्छा किया विदेश से ही इसकी अफवाहों का खंडन कर दिया कि एक साल नहीं खरीदने की अपील करने के बाद जैसे आप जी की सरकार ने सोने पर टैक्स बढ़ाया है, वैसे ही विदेश यात्रा करने वालों पर भी टैक्स लगाने वाली है। सोने की बात दूसरी है, भारत में प्रजा भी थोड़ा-बहुत मुंह मार ही लेती है।

युद्ध और आर्थिक संकट

युद्ध करता कोई और है लेकिन नुकसान झेलते आम लोग और निवेशक हैं यानी जिसकी गलती नहीं, कीमत वो चुकाता है। हाल ही में इजराइल, ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हुए सैन्य टकरावों ने अन्तर्राष्ट्रीय कानून के तहत बल प्रयोग की वैधता पर बहस को फिर से तेज कर दिया है। हालांकि इस चर्चा का बड़ा हिस्सा संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2 (4) के पालन पर केंद्रित रहता है लेकिन एक उतना ही महत्वपूर्ण सवाल अक्सर नजरअंदाज हो जाता है-अवैध बल प्रयोग की आर्थिक कीमत कौन चुकाता है? होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने के बाद से आशंका जताई जाती रही है कि भारत में भी तेल और गैस की कमी हो सकती है। देश की आर्थिक सेहत का मूल्यांकन करने वाली संस्थाओं-रिजर्व बैंक, मूडीज, एसएंडपी, विश्व बैंक, फिच और एशियन डवलपमेंट बैंक ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की विकास दर घटा दी है। जाहिर है कि हमारी अर्थव्यवस्था में संकुचन आया है। वैसे भी भारत अब विश्व की चौथी नहीं, छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसमें और भी गिरावट के आसार हैं। यह मूल्यांकन आसन्न आर्थिक संकट का पहला संकेत है। खुद प्रधानमंत्री ने माना है कि कोरोना महामारी वैश्विक संकट था तो ईरान युद्ध इस दशक का सबसे बड़ा संकट है। प्रधानमंत्री आयात कम करने के पक्षधर हैं, ताकि विदेशी मुद्रा को बचाया जा सके। ईरान युद्ध की शुरुआत में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 720 अरब डॉलर का था, लेकिन युद्ध के करीब 75 दिन के बाद यह भंडार घट कर 690 अरब डॉलर रह गया है। लिहाजा प्रधानमंत्री ने उन खर्चों को कम करने की अपील की है, जिनमें डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। करीब 80 फीसदी कच्चा तेल और 70 फीसदी से अधिक सोने का आयात डॉलर में ही किया जाता है। डॉलर के मुकाबले भारतीय मुद्रा 'रुपए' में 95.28 तक की ऐतिहासिक गिरावट ने संकट को गहरा दिया है। इस समय 'रुपया' दुनिया की दूसरी सबसे कमजोर मुद्रा है, जिसमें 12 फीसदी अवमूल्यन हुआ है। कच्चा तेल महंगा मिलने के कारण भारत को हर रोज 1619 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करने पड़ रहे हैं। आयात बिल में खाद्य तेल पर 1.86 लाख करोड़ और खाद पर 1.38 लाख करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। बाजार में यूरिया, डीएपी की कीमतें दोगुनी बढ़ा दी गई हैं। पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने चेतावनी दी है। भारत की आर्थिक चुनौती विदेशी मुद्रा संकट नहीं है। इसके बजाय 'किफायत और आजीविका का संकट' है। अगर ईरान युद्ध लंबा खिंचता है तो यह और भी बदतर हो सकता है। उनके मुताबिक, हालात बेहतर होने से पहले और ज्यादा बिगड़ने की आशंका है। पीएम मोदी की लोगों से बचत करने की अपील का उन्होंने समर्थन किया है। दिग्गज अर्थशास्त्री ने कहा कि मौजूदा ऊर्जा संकट पहले से ही घरों और आजीविका पर दबाव डाल रहा है। दुनियाभर में ईंधन की बढ़ती कीमतों के कारण ऐसा हुआ है। उन्होंने कहा, 'यह विदेशी मुद्रा का संकट नहीं है। हमारे पास 700 अरब डॉलर का रिजर्व है। ऐसा नहीं है कि हम चीजें खरीद नहीं सकते। यह किफायत और आजीविका का संकट है क्योंकि कीमतें बढ़ती ही हैं। आजीविका पर इसका असर पड़ेगा।'-सुब्रमण्यम ने कहा कि नीति निर्माताओं को विदेशी पूंजी आकर्षित करने पर कम और इस बात पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि ऊर्जा की बढ़ती कीमतों का बोझ समाज के सभी वर्गों में कैसे साझा किया जाए। उन्होंने कहा, 'चुनौती यह है कि इस संकट का बोझ समाज के सभी वर्गों में निष्पक्ष और समान रूप से कैसे साझा किया जाए। ईंधन, गैस और खाद की बढ़ती कीमतें गरीब परिवारों और किसानों को नुकसान पहुंचाएंगी, जब तक कि सरकार इस असर को कम करने के लिए कोई कदम न उठाए।' निजी निवेश अभी भी कमजोर क्यों है? कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक उदय कोटक ने चेतावनी दी है कि लोगों को 'बेहद खराब परिस्थितियों' के लिए तैयार रहना चाहिए। हालांकि सिर्फ भारत ही ऐसा नहीं कर रहा। युद्ध शुरू होने के बाद कई देशों ने अपने उपभोक्ताओं और अर्थव्यवस्था पर असर कम करने के लिए कई कदम उठाए। चीन ने अपनी तेल रिफाइनरियों को अस्थायी रूप से ईंधन निर्यात रोकने का आदेश दिया। ऑस्ट्रेलिया के कुछ राज्यों ने लोगों की गाड़ी कम चलाने के मकसद से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराया घटा दिया। फिलिपींस ने मार्च में राष्ट्रीय इमरजेंसी घोषित की। श्रीलंका ने भी ईंधन राशनिंग लागू की है। अगर भारत निवेश के लिए इतनी अच्छी जगह है और जैसा कि दावा किया जा रहा है, हम 7.5-8 प्रतिशत की दर से बढ़ रहे हैं तो फिर लोग निवेश क्यों नहीं कर रहे हैं?' भारत एक मजबूत ग्रोथ का अनुमान लगा रहा है, जबकि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और निजी निवेश अभी भी सुस्त पड़े हैं। उन्होंने निजी निवेश को फिर से बढ़ाने और निर्यात में प्रतिस्पर्धा को बेहतर बनाने के लिए मिशन मोड पर काम करने की अपील की। हमें उन राज्यों से सीखना होगा जो निजी निवेश आकर्षित करने में कामयाब रहे हैं। दक्षिण भारत के राज्यों ने चीन से काफी निवेश आकर्षित किया है। हमें यह भी देखना होगा कि उन्होंने निवेश आकर्षित करने के लिए क्या नीतियां अपनाई हैं। कृषि को लेकर भी चिंता बनी हुई है। तापमान बहुत ज्यादा है, अल नीनो का असर कम से कम सर्दियों के मौसम में तो जरूर पड़ सकता है। इसलिए हमें निश्चित रूप से इस बात के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। आर्थिक आपातकाल के आसार हैं और भारत सरकार भविष्य में कुछ और कड़े व बड़े फैसले ले सकती है। कुछ पाबंदियां भी जनता को लगाई जा सकती हैं? इस संकट की घड़ी में जनता को भी संयम से काम लेना होगा और किफायत को प्राथमिकता देनी होगी।

भूमि का विनाश क्यों ?

एक तरफ तो हम बढ़ती आबादी का रोना रोते हैं। दूसरी तरफ हम अपनी खेती योग्य जमीन को दैत्यों की तरह बर्बाद कर रहे हैं। इस आत्मघाती विकास से हम अपने भविष्य के लिए भीषण खाद्य संकट पैदा होने के हालात बना रहे हैं। यूं तो आजादी के बाद देश में कृषि, ग्रामीण विकास व जल संसाधन जैसे मंत्रालय बने, जिनके मंत्री और अफसर विदेशों में ज्ञान लेने के बहाने भागते रहे। पर क्या वजह है कि इन सबके होते हुए भी देश में कुल 33 करोड़ हैक्टेयर की तिहाई भूमि बंजर है और लगातार बढ़ रही है। जैसे गोबी मरुस्थल से उड़ी धूल उत्तर चीन से लेकर कोरिया के उपजाऊ मैदानों को ढक रही है, उसी तरह थार मरुस्थल की रेत उत्तर भारत के उपजाऊ मैदानों को निगल रही है। अरावली पर्वत खदानों हद तक धूल भरी आंधियों को रोकने का काम करता है लेकिन अंधाधुंध खनन की वजह से इस पर्वतमाला को नुकसान पहुंच रहा है जिससे यह धूल भरी आंधियों को पूरी तरह नहीं रोक पा रही है। उधर हर साल 84 लाख टन भूमि के पोषक तत्व बाढ़ आदि की वजह से बह जाते हैं। कीटनाशक भी हर साल 1.4 करोड़ वर्ग किमी भूमि की उर्वरता खत्म कर रहे हैं। इसी तरह लवणीयता और क्षारपन भी हर साल 270 हजार वर्ग किमी क्षेत्र को बंजर बना रहे हैं। अनुमान है भी घातक कैमिकल्स, कीटनाशक दवाएं, रासायनिक खाद व जहरीली दवाओं के अमर्यादित प्रयोग से भूमि बंजर बन रही है। साथ ही साथ उद्योगों से निकला प्रदूषित जल वाष्पित होकर ऊपर जाता है। फिर प्रदूषित एवं क्षारीय जल की वर्षा से भूमि पूर्णतया बंजर बन रही है। इसी प्रकार इन दवाओं का प्रयोग होता रहा तो अगले 50 वर्षों में सारे देशवासी भयानक रोगों से ग्रस्त हो जाएंगे। हाल के वर्षों में औद्योगिक कचरे से भी भूमि और जल प्रदूषण की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। उद्योगों से निकले कचरे और प्रदूषित जल को नदियों में छोड़े जाने से भूतलीय और भूमिगत जल प्रदूषित हो गया है। इस तरह के प्रदूषित जल का सिंचाई के लिए इस्तेमाल किए जाने से जमीन भी खराब हो गई है। ताजा अनुमानों के अनुसार इस सबसे 34,500 हैक्टेयर भूमि बुरी तरह प्रभावित हुई है। इसके साथ ही भारी मात्रा में पॉलीथिन और प्लास्टिक का कचरा पृथ्वी की उर्वरता को तेजी से खत्म कर रहा है, क्योंकि यह कचरा गलता नहीं है। इसलिए यह जमीन के लिए बहुत ही घातक है। जिस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगना चाहिए लेकिन न तो केंद्र सरकार ऐसा कर पा रही है और न राज्य सरकारें। जमीन में बोरिंग करके अंधाधुंध पानी खींचने से पृथ्वी के भीतर भूजल स्तर में तेजी से गिरावट आई है जिससे जमीन की नमी खत्म हुई है और रेगिस्तान बढ़ता जा रहा है। फिर भी हमें अक्ल नहीं आ रही। 1947 में देश में एक हजार ट्यूबवैल थे, जिनकी तादाद अब 2.10 करोड़ से भी अधिक है और हर वर्ष बढ़ती जा रही है। इससे भूमिगत पानी की सतह तेजी से नीचे होती जा रही है। इसी तरह औद्योगीकरण के इस दौर में समुद्री तटों के आसपास मनुष्यों के रहने लायक स्थिति नहीं बची है। क्योंकि आए दिन समुद्री पानी से भूमि का कटाव होकर खारा पानी आबादी क्षेत्र में 30 से 100 किमी तक प्रवेश करने लगा है। गुजरात के जामनगर, द्वारिका, जूनागढ़, भावनगर और अमरेली के तटीय गांव उजड़ने की कगार पर हैं। जिसका एकमात्र कारण तटीय जमीन का अतार्किक कटाव किया जाना है। इतना ही नहीं बल्कि देश में हो रहे बेरोकटोक अंधाधुंध खनन से जमीन पोली हो रही है। भूचाल के खतरे बढ़ रहे हैं।

फिर कैसे मिले सुर मेरा-तुम्हारा

ममता को राजनीति में पहला बड़ा ब्रेक बेशक राजीव गांधी ने दिया, लेकिन वामपंथियों के साथ राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेसी सहयोग ने उन्हें बाद के दिनों में गांधी-नेहरू परिवार से दूर कर दिया। हालिया हार के बावजूद अपनी संघर्षशीलता के चलते ममता विपक्षी राजनीति का अब भी बड़ा चेहरा है। विधानसभा चुनावों में बड़े विपक्षी चेहरों की बड़ी नाकामी से विपक्षी खेमे में खलबली मच गई है। बंगाल की शेरनी कही जाने वाली ममता बनर्जी की हार ने विपक्षी खेमे के उन दलों के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई हैं, जो इन चुनावों से बेपरवाह थे। केरल की गठबंधन सरकार में वापसी की वजह से कांग्रेस थोड़ी राहत में भले ही हो, लेकिन ज्यादातर क्षेत्रीय दलों को अपने अस्तित्व पर खतरा नजर आने लगा है। तमिलनाडु में सत्ता की चाहत में विपक्षी गठबंधन टूट भी चुका है। कांग्रेस के हाथ ने डीएमके का बरसों पुराना साथ छोड़ नवेली टीवीके का दामन थाम लिया है। दूसरी तरफ धांधली का आरोप लगाने के साथ ही ममता बनर्जी को विपक्षी एकता, खासकर इंडिया ब्लॉक की याद आने लगी है। अब उन्हें विपक्षी एकता मजबूत करने की याद भी आने लगी है। दिलचस्प यह है कि अतीत में इंडिया ब्लॉक की एकता से बेपरवाह रहीं ममता को अब उसी की बहुत याद आने लगी है। वैसे विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस की ओर से भी कम गलतियां नहीं हुई हैं। राहुल गांधी का पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बढ़त के लिए ममता को खुलेआम जिम्मेदार ठहराना एक तरह से तृणमूल की ताबूत का कील ही साबित हुआ। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि विपक्षी एकता का विचार फिर से परवान चढ़ सकता है ? अतीत में एकता को लेकर जिस तरह विपक्षी खेमे में एक-दूसरे को शह और मात देने का खेल चला है, उससे क्या मुकम्मल एकता की उम्मीद बनती है? 2024 के आम चुनावों के पहले विपक्षी राजनीति को एक मंच पर लाने और भाजपा विरोधी मोर्चा बनाने की कोशिश तो हुई, लेकिन आपसी टकराव और वर्चस्व के चलते यह हकीकत नहीं बन पाया। 23 जून 2023 को पटना में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुआई में विपक्षी दलों की बैठक में इंडिया ब्लॉक बनाने का फैसला तो हुआ,लेकिन नेतृत्व के मुद्दे पर एक राय नहीं बन पाई। नीतीश कुमार ने खुलकर भले ही कभी नहीं कहा, लेकिन उनकी चाहत थी कि विपक्षी गठबंधन का संयोजक उन्हें बनाया जाय। लेकिन कांग्रेसी आलाकमान की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। दरअसल कांग्रेस विपक्षी राजनीति की लगाम खुद के हाथ में ही रखना चाहती है। नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और एमके स्टालिन का साथ तो उसे चाहिए, लेकिन इनमें से किसी का भी नेतृत्व उसे गवारा नहीं। अपने पहले परिवार की पूरी स्वीकार्यता भले हो ना हो, लेकिन अगुआई कांग्रेस को ही चाहिए। यही वजह है कि विपक्षी राजनीति के सबसे ज्यादा स्वीकार्य चेहरा रहे नीतीश कुमार ने निराश में उसी मोदी का हाथ थाम लिया, जिससे वे दूर हो चुके थे। इसके बाद का इतिहास सबको पता है। ममता को राजनीति में पहला बड़ा ब्रेक बेशक राजीव गांधी ने दिया, लेकिन वामपंथियों के साथ राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेसी सहयोग ने उन्हें बाद के दिनों में गांधी-नेहरू परिवार से दूर कर दिया। हालिया हार के बावजूद अपनी संघर्षशीलता के चलते ममता विपक्षी राजनीति का अब भी बड़ा चेहरा है उनकी अपनी छवि अक्सर राहुल गांधी पर भी भारी पड़ती है। इंडिया ब्लॉक के विचार के वक्त पूर्व कांग्रेसी होने के नाते ममता को पता था कि कांग्रेस अपने हाथ में नेतृत्व बनाए रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी, इसीलिए उन्होंने ही नीतीश कुमार और लालू यादव को पहली बैठक पटना में कराने का सुझाव दिया था। बाद के दिनों में कांग्रेस ने जैसी चाल चली, उससे विपक्षी एकता का राग बेसुरा हो गया। जिसका नतीजा लोकसभा चुनाव नतीजों में दिखा भी। विपक्ष को उसी वक्त चेतना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। असर यह हुआ कि हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मार ली। बाकी कसर बीते विधानसभा चुनावों ने पूरी कर दी है। गौर करने की बात है कि जब भी सत्ता पक्ष के उभार में विपक्ष बढ़ जाता है, उसकी एकता की छटपटाहट बढ़ जाती है। ज्यादातर यह अस्तित्व संकट टालने का यह फौरी उपाय होता है। तब वह हार के बाद वोटों के गुणा-गणित में जुट जाता है। फिर उसे इलहाम होता है कि अगर वह एक रहता तो वह भारी पड़ता। 1962 के आम चुनावों में नेहरू को फूलपुर की सीट पर सीधी चुनौती में हार मिलने के बाद लोहिया को भी कुछ ऐसा ही लगा। तब भारी उत्सुकता और उत्साह के बावजूद लोहिया हार गए थे। इसके बाद उन्होंने गैर कांग्रेसवाद का विचार दिया। तब कांग्रेस को 44 प्रतिशत से कुछ ज्यादा वोट मिले थे। लोहिया को लगा कि विरोध में पड़े 56 प्रतिशत वोटों को अगर एक किया जाता तो नतीजे कुछ और होते। गैर कांग्रेसवाद के बैनर के तले उन्होंने 1963 के उपचुनावों और 1967 के आम चुनावों में इसे आजमाया। इसका असर यह हुआ कि आठ राज्यों से कांग्रेस की विदाई हो गई। तब से सत्ता में आने वाली पार्टी के खिलाफ बाकी विपक्ष की एकता के सुर उठने की परंपरा बन गई है। कभी यह कांग्रेस के खिलाफ होता था, जिसमें वामपंथी और जनसंघ- बीजेपी भी शामिल रहते थे, अब यह भाजपा के खिलाफ हो रहा है। प. बंगाल के बीते विधानसभा चुनाव में ममता को जहां करीब 42 प्रतिशत वोट मिला है, वहीं बीजेपी को करीब 46 प्रतिशत। कांग्रेस को 2.97 और वामपंथियों को 4.45 प्रतिशत वोट मिले हैं। गैर बीजेपी वोटों को मिला दें तो यह आंकड़ा 49 प्रतिशत से ज्यादा हो जाता है। चुनावी राजनीति में सात प्रतिशत का अंतर बड़ा होता है। अब विपक्षी खेमे को लग रहा है कि अगर वे एक होते तो बीजेपी को ऐसी जीत नहीं मिलती। वैसे चुनावी गणित सामान्य गणित की तरह नहीं होता। 2018 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस से बीजेपी को पांच लाख से ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन सीटों के मामले में वह पिछड़ गई थी।

चुनावी मैदान में जब सिर्फ दो खेमे होते हैं, तब मतदाताओं के बीच लंबवत ध्रुवीकरण हो जाता है। तब बिलगाव वाले आंकड़े भी बदल जाते हैं। 2014 के संसदीय चुनाव में उत्तर प्रदेश में ऐसा साफ दिखा, जब बीजेपी सब पर भारी रही। संसदीय चुनाव में सफलता के लिहाज से देखें तो कांग्रेस की 99 सीटों के बाद 37 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी विपक्ष का दूसरा बड़ा दल है। तीसरे नंबर पर 29 सीटों के साथ ममता ही है। इंडिया ब्लॉक की पहली बैठक के पीछे ममता का भी विचार था, फिर भी ना तो लोकसभा और ना ही विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस या ब्लॉक के दूसरे दलों को तवज्जो दिया। तमिलनाडु में डीएमके के साथ कांग्रेस की खींचतान जारी रही। विपक्ष के किसी भी दल ने एकता की कीमत पर त्याग स्वीकार नहीं किया। विपक्षी खेमे का संकट यह है कि वह अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में सहयोगियों से हिस्सेदारी बांटना ही नहीं चाहता। मजबूत एकता के लिए विपक्ष के पास राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य साफ छवि वाला चेहरा होना जरूरी है। लेकिन विपक्ष के पास ऐसा चेहरा है भी नहीं। ममता बड़ी नेता तो हैं, लेकिन उनकी तुनकमिजाजी उन्हें सर्वमान्य नेतृत्व मानने के राह की बड़ी बाधा है। राहुल मोदी-शाह की जोड़ी को चाहे जिस अंदाज में चुनौती दें, मोदी विरोधी बौद्धिकों को उनका यह अंदाज चाहे जितना भी पसंद हो, लेकिन आमजन को उनमें कई बार बचकानापन नजर आता है तो कई मर्तबा अहमन्य। स्टालिन चाहे जितनी अच्छी तमिल बोलें, लेकिन राष्ट्रीय स्तर स्वीकार्यता के लिए वे अयोग्य हैं। इसी तरह केजरीवाल के पास बड़ा आधार नहीं है। यही बात अखिलेश यादव की तो, वे भी जमीनी राजनीति के बजाय बयानों के गुब्बारे उड़ाने के उस्ताद होते गए हैं। आपसी अहं के टकराव के चलते नीतीश विपक्षी खेमा छोड़ चुके हैं दूसरी बड़ी नेता ममता को चुनावी मैदान में करारी शिकस्त मिल गई है। अखिलेश को भी अगले साल उत्तर प्रदेश के सियासी मैदान में बीजेपी से दो-दो हाथ करना है। बीजेपी की कोशिश उन्हें तीसरी बार शिकस्त देने की होगी। अगर वह ऐसा करने में कामयाब रही तो उसके सामने दूर-दूर तक कोई चुनौती नहीं होगी। ऐसे में विपक्षी खेमे का संकट बड़ा है। अतीत के विपक्षी व्यवहार से नहीं लगता कि शायद ही भविष्य में कोई मजबूत मोर्चा बन सके। खुलकर विपक्षी खेमा भले ही ना कहे, लेकिन अंदर ही अंदर वह जरूर गुनगुना रहा है, कैसे मिले सुर हमारा-तुम्हारा....ममता को राजनीति में पहला बड़ा ब्रेक बेशक राजीव गांधी ने दिया, लेकिन वामपंथियों के साथ राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेसी सहयोग ने उन्हें बाद के दिनों में गांधी-नेहरू परिवार से दूर कर दिया। हालिया हार के बावजूद अपनी संघर्षशीलता के चलते ममता विपक्षी राजनीति का अब भी बड़ा चेहरा है। विधानसभा चुनावों में बड़े विपक्षी चेहरों की बड़ी नाकामी से विपक्षी खेमे में खलबली मच गई है। बंगाल की शेरनी कही जाने वाली ममता बनर्जी की हार ने विपक्षी खेमे के उन दलों के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई हैं, जो इन चुनावों से बेपरवाह थे। केरल की गठबंधन सरकार में वापसी की वजह से कांग्रेस थोड़ी राहत में भले ही हो, लेकिन ज्यादातर क्षेत्रीय दलों को अपने अस्तित्व पर खतरा नजर आने लगा है। तमिलनाडु में सत्ता की चाहत में विपक्षी गठबंधन टूट भी चुका है। कांग्रेस के हाथ ने डीएमके का बरसों पुराना साथ छोड़ नवेली टीवीके का दामन थाम लिया है। दूसरी तरफ धांधली का आरोप लगाने के साथ ही ममता बनर्जी को विपक्षी एकता, खासकर इंडिया ब्लॉक की याद आने लगी है। अब उन्हें विपक्षी एकता मजबूत करने की याद भी आने लगी है। दिलचस्प यह है कि अतीत में इंडिया ब्लॉक की एकता से बेपरवाह रहीं ममता को अब उसी की बहुत याद आने लगी है। वैसे विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस की ओर से भी कम गलतियां नहीं हुई हैं। राहुल गांधी का पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बढ़त के लिए ममता को खुलेआम जिम्मेदार ठहराना एक तरह से तृणमूल की ताबूत का कील ही साबित हुआ। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि विपक्षी एकता का विचार फिर से परवान चढ़ सकता है ?

अतीत में एकता को लेकर जिस तरह विपक्षी खेमे में एक-दूसरे को शह और मात देने का खेल चला है, उससे क्या मुकम्मल एकता की उम्मीद बनती है? 2024 के आम चुनावों के पहले विपक्षी राजनीति को एक मंच पर लाने और भाजपा विरोधी मोर्चा बनाने की कोशिश तो हुई, लेकिन आपसी टकराव और वर्चस्व के चलते यह हकीकत नहीं बन पाया। 23 जून 2023 को पटना में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुआई में विपक्षी दलों की बैठक में इंडिया ब्लॉक बनाने का फैसला तो हुआ,लेकिन नेतृत्व के मुद्दे पर एक राय नहीं बन पाई।

प्रयागराज में दो लेन फ्लाईओवर निर्माण से 50 लाख लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हुए लाभान्वित

उत्तर प्रदेश में तीव्र गति से हो रहे शहरी विकास और बढ़ती जनसंख्या के साथ यातायात का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। धार्मिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रयागराज भी लंबे समय से इस चुनौती का सामना कर रहा था। विशेष रूप से माघ मेला, कुंभ मेला और अन्य धार्मिक आयोजनों के दौरान शहर की प्रमुख सड़कों पर भारी भीड़ और जाम की स्थिति आम हो जाती थी। इसी समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में उत्तर प्रदेश सेतु निगम द्वारा शहर उत्तरी विधानसभा क्षेत्र में आलोपी देवी मंदिर से बघाड़ा चौराहे तक आलोपीबाग फ्लाईओवर के समानांतर दो लेन फ्लाईओवर का निर्माण कराया गया है। यह परियोजना प्रयागराज की यातायात व्यवस्था को आधुनिक, सुरक्षित और अधिक सुगम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। प्रयागराज का आलोपीबाग क्षेत्र शहर के सबसे व्यस्त मार्गों में शामिल है। यहां प्रतिदिन हजारों वाहनों का आवागमन होता है और धार्मिक आयोजनों के समय यह संख्या कई गुना बढ़ जाती है। पहले एकमात्र फ्लाईओवर पर अत्यधिक दबाव के कारण लोगों को लंबे समय तक जाम में फंसना पड़ता था। नए समानांतर दो लेन फ्लाईओवर के निर्माण से अब यातायात का भार विभाजित होगा, जिससे आवागमन अधिक तेज, सुरक्षित और व्यवस्थित हो सकेगा। इससे स्थानीय नागरिकों के साथ-साथ बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं और यात्रियों को भी बड़ी राहत मिलेगी। रुपये 54.31 करोड़ की लागत से निर्मित यह फ्लाईओवर लगभग 780.484 मीटर लंबा और 7.50 मीटर चौड़ा है। इसे आधुनिक इंजीनियरिंग तकनीकों और उच्च गुणवत्ता मानकों के अनुरूप तैयार किया गया है, ताकि भविष्य में बढ़ते यातायात दबाव को भी प्रभावी ढंग से संभाला जा सके। परियोजना का निर्माण कार्य मार्च 2024 में प्रारंभ हुआ और नवंबर 2024 में सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया। कम समय में गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य पूरा होना उत्तर प्रदेश सेतु निगम की कार्यकुशलता, तकनीकी क्षमता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों, यातायात प्रबंधन और स्थानीय नागरिकों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया। यही कारण है कि परियोजना न केवल समयबद्ध तरीके से पूरी हुई, बल्कि निर्माण गुणवत्ता के स्तर पर भी यह एक उत्कृष्ट उदाहरण बनकर उभरी है। प्रयागराज विश्व प्रसिद्ध धार्मिक आयोजनों का केंद्र है। कुंभ और माघ मेले में देश-विदेश से करोड़ों श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। ऐसे अवसरों पर शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होती है। आलोपीबाग क्षेत्र में नए फ्लाईओवर के निर्माण से अब संगम स्नान व मेले और अन्य बड़े आयोजनों के दौरान यातायात संचालन अधिक व्यवस्थित और नियंत्रित हो सकेगा। इससे श्रद्धालुओं की यात्रा आसान होगी और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को भी मजबूती मिलेगी। यह परियोजना केवल यातायात सुधार तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रयागराज के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी नई गति प्रदान करेगी। बेहतर सड़क और पुल अवसंरचना किसी भी शहर की प्रगति की आधारशिला होती है। फ्लाईओवर बनने से व्यापारिक क्षेत्रों, शैक्षणिक संस्थानों और आवासीय इलाकों के बीच संपर्क अधिक मजबूत हुआ है। इससे स्थानीय व्यापारियों, विद्यार्थियों, नौकरीपेशा लोगों और आम नागरिकों को तेज और सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिल रही है। और समय और संसाधनों दोनों की बचत हो रही है। इस परियोजना का लाभ केवल प्रयागराज तक सीमित नहीं है बल्कि रीवा, जौनपुर, लखनऊ, वाराणसी और मिर्जापुर जैसे क्षेत्रों से आने-जाने वाले यात्रियों को भी बेहतर कनेक्टिविटी और कम यात्रा समय का लाभ मिल रहा है। इस फ्लाईओवर से लगभग 50 लाख लोग प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हो रहे हैं। इससे क्षेत्रीय संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को भी नई ऊर्जा मिल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में आधुनिक आधारभूत संरचना के विकास को प्राथमिकता दे रही है। सड़क, पुल और फ्लाईओवर निर्माण की अनेक परियोजनाएं तेजी से पूरी की जा रही हैं। प्रयागराज में निर्मित यह दो लेन फ्लाईओवर उसी विकासवादी दृष्टिकोण का सशक्त उदाहरण है, जिसका उद्देश्य केवल निर्माण कार्य कराना नहीं, बल्कि नागरिकों को सुरक्षित, सुविधाजनक और समयबद्ध यातायात व्यवस्था उपलब्ध कराना है। फ्लाईओवर निर्माण का सकारात्मक प्रभाव पर्यावरण पर भी दिखाई देगा। यातायात जाम कम होने से वाहनों का अनावश्यक ईंधन खर्च घटेगा और प्रदूषण में कमी आएगी। पहले जहां लोगों का बहुमूल्य समय जाम में व्यर्थ होता था, अब वे कम समय में अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। इससे नागरिकों के जीवन स्तर और शहरी यातायात व्यवस्था दोनों में सुधार होगा। उत्तर प्रदेश में आधारभूत संरचना के तीव्र विकास के क्रम में सेतु परियोजना प्रयागराज जनपद में निर्मित की जा रही जीटी रोड से एयरपोर्ट रोड तक को रेल उपरिगामी सेतु परियोजना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में सामने आई है। यह परियोजना न केवल शहर के यातायात दबाव को कम करेगी, बल्कि प्रयागराज को अधिक व्यवस्थित, सुरक्षित और आधुनिक यातायात सुविधा प्रदान करने में भी सहायक सिद्ध होगी। तेजी से बढ़ते शहरीकरण, वाहनों की संख्या में निरंतर वृद्धि तथा रेलवे क्रॉसिंग पर लगने वाले जाम की समस्या को देखते हुए इस परियोजना की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। अब इस महत्वाकांक्षी परियोजना के पूर्ण होने से लाखों नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होगा। प्रदेश सरकार द्वारा आधारभूत ढांचे के विकास को प्राथमिकता दिए जाने के परिणामस्वरूप यह परियोजना आज धरातल पर साकार हो रही है। यह परियोजना प्रयागराज शहर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र तथा फूलपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। यह परियोजना जनपद प्रयागराज में जीटी रोड से एयरपोर्ट रोड के निकट सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन पर 04 लेन रेल उपरिगामी सेतु तथा जीटी रोड जंक्शन पर चौफटका से कानपुर की ओर 02 लेन फ्लाईओवर के निर्माण से संबंधित है। परियोजना का उद्देश्य शहर के पश्चिमी क्षेत्र में यातायात को सुगम बनाना तथा रेलवे क्रॉसिंग के कारण होने वाली देरी और दुर्घटनाओं की संभावनाओं को समाप्त करना है। यह सेतु परियोजना प्रयागराज के शहरी विकास को नई दिशा देने वाली मानी जा रही है। इस परियोजना के अंतर्गत बनाये जाने वाला सेतु रेल उपरिगामी सेतु (आरओबी) के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस प्रकार के सेतु का मुख्य उद्देश्य रेलवे लाइन के ऊपर से निर्बाध यातायात उपलब्ध कराना होता है। इससे लोगों को रेलवे फाटक बंद होने की स्थिति में लंबे समय तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। साथ ही आपातकालीन सेवाओं जैसे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड एवं सुरक्षा वाहनों की आवाजाही भी अधिक तेज और सुरक्षित हो सकेगी। प्रदेश सरकार परियोजना की गुणवत्ता और दीर्घकालिक उपयोगिता को सुनिश्चित करने के लिए गंभीरता से कार्य कर रही है। इस परियोजना की कुल लागत 398.28 करोड़ रुपये है। इतनी बड़ी धनराशि का निवेश प्रयागराज के शहरी यातायात तंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। परियोजना की कुल लंबाई 1583.876 मीटर है, जिससे भारी वाहनों सहित सामान्य यातायात का सुचारू संचालन संभव हो सकेगा। निर्धारित समयसीमा के भीतर कार्य पूर्ण होने पर यह परियोजना प्रयागराज के यातायात ढांचे में क्रांतिकारी परिवर्तन लायेगी। आधुनिक इंजीनियरिंग तकनीकों के उपयोग से तैयार किया जा रहा यह सेतु मजबूत, सुरक्षित तथा दीर्घकालिक उपयोग के अनुरूप बनाया गया है। इस परियोजना से लगभग 80 लाख जनसंख्या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होगी। प्रयागराज जैसे धार्मिक, शैक्षणिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर में सुगम यातायात व्यवस्था का व्यापक प्रभाव दिखाई देगा। विशेष रूप से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन तथा प्रमुख संस्थानों तक पहुंच आसान होने से नागरिकों, छात्रों, पर्यटकों और व्यापारियों को अत्यधिक सुविधा प्राप्त होगी। परियोजना के लाभार्थी क्षेत्रों में एयरपोर्ट एन्क्लेव, इंडियन ऑयल परिसर, ट्रिपल आईटी, शम्भुनाथ तकनीकी संस्थान, भारतीय तिब्बती पुलिस मुख्यालय, वायुसेना कॉलोनी तथा चित्रकूट धाम, बांदा और मध्य प्रदेश की ओर जाने वाले मार्ग शामिल हैं। यह परियोजना क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत करने के साथ-साथ आर्थिक गतिविधियों को भी गति प्रदान करेगी। इससे व्यापार, पर्यटन और शिक्षा क्षेत्र को प्रत्यक्ष लाभ मिलने की संभावना है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने वन्दना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साउथ पंचशील एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2001/09862)

दिल्ली--एनसीआर को मिलेगा हाईस्पीड कनेक्टिविटी कॉरिडोर, सीएम रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया निरीक्षण

नई दिल्ली । दिल्ली-एनसीआर में ट्रैफिक जाम की समस्या कम करने और अलग-अलग शहरों के बीच सफर आसान बनाने के लिए निर्माणाधीन डीएनडी-फरीदाबाद-सोहना एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है. बुधवार को इस महत्वाकांक्षी परियोजना का निरीक्षण केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया. उनके साथ कई केंद्रीय राय मंत्री, सांसद और हरियाणा-दिल्ली सरकार के मंत्री भी मौजूद रहे. करीब 59 किलोमीटर लंबे इस हाईवे का निर्माण लगभग 4463 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है. यह हाईवे दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोहना को तेज रफ्तार कनेक्टिविटी देगा. परियोजना के पूरा होने के बाद दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे और जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंच काफी आसान हो जाएगी. यह हाईवे भारतमाला परियोजना के तहत विकसित किया जा रहा है. इसे 6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड कॉरिडोर के रूप में तैयार किया जा रहा है, जिससे वाहनों की आवाजाही तेज और सुरक्षित हो सके. इस प्रोजेक्ट में आधुनिक इंजीनियरिंग तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे इसे भविष्य की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया जा सके. सरकार का कहना है कि इस हाईवे के चालू होने से दिल्ली-एनसीआर में ट्रैफिक का दबाव कम होगा और लोगों का सफर समय भी काफी घट जाएगा. खास तौर पर दक्षिण दिल्ली, फरीदाबाद और गुरुग्राम से जेवर एयरपोर्ट जाने वालों को बड़ी राहत मिलेगी. इस परियोजना की सबसे बड़ी खासियत 140 मीटर लंबा नेटवर्क आर्च ब्रिज है. इसे भारत की सबसे आधुनिक स्टील ब्रिज संरचनाओं में गिना जा रहा है. इस पुल को टाइड-आर्च तकनीक और क्रॉस्ड हैंगर सिस्टम के जरिए डिजाइन किया गया है, जिससे इसकी मजबूती और सुरक्षा बढ़ती है. इसके अलावा प्रोजेक्ट में प्रीकास्ट सेगमेंटल

कंस्ट्रक्शन, लॉन्चिंग गर्डर, हाई-स्ट्रेंथ स्टील, हाई-डैम्पिंग रबर बेयरिंग और आधुनिक एक्सपेंशन जॉइंट जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है. अधिकारियों के मुताबिक इन तकनीकों से हाईवे यादा टिकाऊ और सुरक्षित बनेगा. इस परियोजना में पर्यावरण संरक्षण पर भी खास ध्यान दिया गया है. ओखला और गाजीपुर लैंडफिल की बायो-माइनिंग से निकली करीब 2 लाख मीट्रिक टन निष्क्रिय सामग्री का इस्तेमाल सड़क निर्माण में किया गया है. इससे प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता कम हुई है. हाईवे के किनारे नॉइज बैरियर, लैंडस्केपिंग और बड़े स्तर पर पौधारोपण का काम भी किया जा रहा है. अधिकारियों का कहना है कि यह परियोजना आधुनिक विकास के साथ पर्यावरण संतुलन का भी उदाहरण बनेगी. परियोजना का एक बड़ा उद्देश्य नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी जेवर एयरपोर्ट तक आसान और तेज कनेक्टिविटी देना है. इसके लिए फरीदाबाद के चंदावली गांव से लेकर गौतम बुद्ध नगर के दयानापुर तक नया एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है. करीब 31 किलोमीटर लंबे इस हिस्से का निर्माण 2360 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है. इस सड़क को यमुना एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा. इससे उत्तर भारत से आने वाला ट्रैफिक सीधे जेवर एयरपोर्ट तक पहुंच सकेगा और दिल्ली पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा. इस परियोजना के तहत डीएनडी-सोहना हाईवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे और डीएफसीसी कॉरिडोर पर चार बड़े इंटरचेंज बनाए जा रहे हैं. साथ ही एक एलिवेटेड कॉरिडोर और आठ लेन का रेलवे ओवर ब्रिज भी तैयार किया जा रहा है. इन इंटरचेंजों के बनने से फरीदाबाद, गुरुग्राम और दक्षिण दिल्ली से नोएडा एयरपोर्ट तक सफर काफी तेज हो जाएगा. लोगों को बार-बार ट्रैफिक जाम में फंसना नहीं पड़ेगा. विशेषज्ञों का मानना है कि इस हाईवे से एनसीआर में व्यापार, उद्योग और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को बड़ा फायदा होगा. बेहतर सड़क नेटवर्क बनने से माल ढुलाई आसान होगी और नए निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा. यह कॉरिडोर फरीदाबाद मास्टर प्लान 2031 क्षेत्र से होकर गुजर रहा है, जिसे भविष्य के शहरी विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है. ऐसे में आने वाले वर्षों में इस इलाके में तेजी से विकास होने की संभावना जताई जा रही है. निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का धन्यवाद किया. उन्होंने कहा कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे लिंक परियोजना दिल्ली के भविष्य को बेहतर बनाने वाली बड़ी सौगात है. रेखा गुप्ता ने कहा कि यह परियोजना दिल्ली-एनसीआर की तस्वीर बदल देगी और लाखों लोगों के लिए यात्रा को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाएगी. उनके मुताबिक आने वाले समय में यह हाईवे राजधानी और आसपास के इलाकों के विकास में बड़ी भूमिका निभाएगा.

अरविंद केजरीवाल को चुनाव लड़ने से अयोग्य करने की जनहित याचिका, हाई कोर्ट से दिया बड़ा फैसला

नई दिल्ली । दिल्ली हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक को चुनाव लड़ने से डिस्क्वालिफाई करने और आप पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल जनहित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देवेन्द्र उपाध्याय की बेंच ने सुनवाई की. कोर्ट ने इस जनहित याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा याचिका में लगाए गए आरोप में कोई कानूनी दम नहीं है. लिहाजा इस याचिका पर कोई आदेश जारी करने का कोई औचित्य नहीं बनता है. याचिकाकर्ता की ओर से वकील ने कहा कि केजरीवाल समेत अन्य लोगों ने अदालत की कार्यवाही को बदनाम करने और उसे विवादित बनाने की कोशिश कर रहे हैं. इस पर कोर्ट ने कहा कि आप चाहते हैं कि हम चुनाव आयोग को किसी राजनीतिक पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का आदेश दें? लेकिन क्या कानून में राजनीतिक पार्टी को डि-रजिस्टर करने का कोई प्रावधान है. अगर है तो उसका पूरा कानूनी ढांचा क्या है? इस पर वकील ने जवाब दिया कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में राजनीतिक दल को डि-रजिस्टर करने का सीधा प्रावधान नहीं है.

कानून इस मामले में साफ है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में तीन असाधारण परिस्थितियों का जिक्र किया गया है जिनमें राजनीतिक दल का पंजीकरण रद्द किया जा सकता है. वकील ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा बताए गए तीन अपवादों का हवाला देते हुए अदालत को उन स्थितियों की जानकारी दी. इस पर कोर्ट ने कहा कि पहली दो स्थितियों में यह मामला फिट नहीं बैठता. तीसरी स्थिति यह है कि किसी राजनीतिक दल का पंजीकरण तभी रद्द किया जा सकता है, जब उसे क्र या इसी तरह के किसी कानून के तहत गैरकानूनी संगठन घोषित किया गया हो. वकील ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29(5) कहती है कि जब कोई पार्टी रजिस्टर होती है, तो उसे लिखित रूप से यह वचन देना होता है कि वह संविधान और उसके मूल सिद्धांतों का पालन करेगी. वकील ने तर्क दिया कि अगर कोई पार्टी इन शर्तों का उल्लंघन करती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई या डि-रजिस्ट्रेशन की मांग उठ सकती है.

याचिकाकर्ता के वकील ने इसके बाद जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि यही उनकी याचिका का आधार है. इस पर अदालत ने कहा कि सबसे पहले यह साबित करना होगा कि किसी अदालत के आदेश के बाद चुनाव आयोग को किसी राजनीतिक दल का पंजीकरण रद्द करने का अधिकार है? कोर्ट ने साफ किया कि केवल किसी फैसले का हवाला देना काफी नहीं है बल्कि यह भी दिखाना जरूरी है कि कानून के तहत अदालत के आदेश के बाद चुनाव आयोग किसी पार्टी के खिलाफ ऐसा कदम उठा सकता है. वकील ने कहा, अगर किसी व्यक्ति को भारतीय संविधान पर भरोसा नहीं है तो मेरी राय में वह चुनाव नहीं लड़ सकता.

मैं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक की बात कर रहा हूं. कोर्ट ने कहा कि इससे किसी राजनीतिक पार्टी का पंजीकरण रद्द कैसे होगा? इस पर वकील ने कहा, मेरी दूसरी मांग भी है कि केजरीवाल और अन्य को संसद और विधानसभा चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया जाए. किसी राजनीतिक दल का सदस्य होकर अदालत की कार्यवाही को बदनाम नहीं कर सकता. कोर्ट ने कहा कि अगर किसी नेता ने अदालत के खिलाफ बयान दिया है तो उसके लिए अलग कानूनी प्रक्रिया अवमानना की कार्रवाई. केवल इस आधार पर किसी राजनीतिक पार्टी को खत्म करना या नेताओं को चुनाव लड़ने से रोकना उचित नहीं है. कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक दलों के रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया कानून में तय है और इस मामले में दायर याचिका उसी कानूनी व्यवस्था को सही ढंग से समझे बिना दाखिल की गई है.

क्या टेट्रा पैक में शराब बिक्री होगी बंद? सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा मामला, केंद्र समेत कई पक्षों को नोटिस

नई दिल्ली । में शराब की बिक्री और पैकेजिंग को लेकर एक अहम जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार समेत कई पक्षों को नोटिस जारी किया है। याचिका में मांग की गई है कि टेट्रा पैक, सैशे और छोटे पाउच जैसी पैकेजिंग में शराब की बिक्री पर तत्काल रोक लगाई जाए। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए सहमति भी दे दी है। यह याचिका संगठन कम्युनिटी अगेंस्ट ड्रंकन ड्राइविंग की ओर से दायर की गई है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील विपिन नायर ने शराब की पैकेजिंग को लेकर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मौजूदा एक्साइज नियमों में बोतल की परिभाषा स्पष्ट नहीं है, जिसके कारण कंपनियां ऐसे पैकेजिंग डिजाइन का इस्तेमाल कर रही हैं जिससे उपभोक्ताओं में भ्रम पैदा हो रहा है। नायर ने अदालत से कहा कि वे फलों के जूस और शराब में भ्रम पैदा कर रहे हैं। बोतलों और पैकिंग पर सेब जैसे फलों की तस्वीरें लगाई जाती हैं, जबकि अंदर वोदका जैसी

शराब होती है। उन्होंने तर्क दिया कि इस तरह की पैकेजिंग खासकर युवाओं और बच्चों को भ्रमित कर सकती है और नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना राय का संवैधानिक कर्तव्य है। याचिका में केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है कि वह सभी रायों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक समान नीति तैयार करे। इसमें टेट्रा पैक, सैशे और जूस जैसे दिखने वाले पैकेजिंग में शराब की बिक्री पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई है। साथ ही याचिका में यह भी कहा गया है कि रायों के एक्साइज कानूनों, नियमों और नीतियों में संशोधन कर बॉटलिंग की एक समान परिभाषा तय की जाए। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि शराब केवल कांच की बोतलों या अन्य स्पष्ट रूप से अलग दिखने वाले कंटेनरों में ही बेची जानी चाहिए, ताकि उपभोक्ताओं में किसी तरह का भ्रम न हो।

नई दिल्ली स्टेशन पर भीड़ प्रबंधन का नया फॉर्मूला, रंगों से चलेगा सही दिशा का पता

नई दिल्ली । नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की बढ़ती संख्या और लगातार बढ़ रही भीड़ को देखते हुए रेलवे ने एक नई व्यवस्था लागू की है. अब स्टेशन पर अलग-अलग रंगों के संकेतक बोर्ड लगाए गए हैं, जिनकी मदद से यात्री आसानी से अपने प्लेटफॉर्म और सही प्रवेश द्वार तक पहुंच सकेंगे. रेलवे प्रशासन ने स्टेशन के भीतर यात्रियों की आवाजाही को व्यवस्थित करने के लिए टिकट श्रेणी के आधार पर प्रवेश व्यवस्था तैयार की है. अनारक्षित टिकट वाले यात्रियों को अलग गेट से प्रवेश दिया जाएगा, जबकि आरक्षित टिकट धारकों के लिए अलग मार्ग निर्धारित किए गए हैं.

इस व्यवस्था का उद्देश्य प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के दौरान होने वाली अफरा-तफरी को कम करना है. स्टेशन परिसर में लगाए गए नए बोर्डों में तीन रंगों का इस्तेमाल किया गया है. पीले रंग के संकेत अनारक्षित टिकट लेकर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए लगाए गए हैं, जिनके जरिए वे प्लेटफॉर्म 1 से 16 तक पहुंच सकेंगे. बैंगनी रंग के बोर्ड प्लेटफॉर्म 1 से 15 तक जाने वाले आरक्षित यात्रियों के

लिए लगाए गए हैं, जबकि हरे रंग के संकेतक प्लेटफॉर्म 16 की ओर जाने वाले आरक्षित यात्रियों का मार्गदर्शन करेंगे. नई व्यवस्था के तहत गेट नंबर भी तय कर दिए गए हैं. अनारक्षित टिकट वाले यात्रियों को गेट नंबर 12 से प्रवेश मिलेगा.

वहीं प्लेटफॉर्म 1 से 15 तक जाने वाले आरक्षित यात्रियों के लिए गेट नंबर 8 और 11 निर्धारित किए गए हैं. प्लेटफॉर्म 16 के यात्रियों को गेट नंबर 7 और 10 से प्रवेश दिया जाएगा. रेलवे ने इन गेटों के बाहर रंग आधारित दिशा सूचक बोर्ड भी लगा दिए हैं ताकि यात्रियों को भ्रम की स्थिति का सामना न करना पड़े. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन देश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में गिना जाता है. यहां प्रतिदिन करीब 300 से अधिक ट्रेनों का संचालन होता है और बड़ी संख्या में यात्री आवागमन करते हैं. त्योहारों, छुट्टियों और विशेष अवसरों पर स्टेशन परिसर में भीड़ कई गुना बढ़ जाती है, जिससे व्यवस्थाएं संभालना चुनौती बन जाता है. भीड़ नियंत्रण के लिए रेलवे ने पिछले वर्ष स्टेशन परिसर में स्थायी यात्री सुविधा शिविर भी शुरू किया था. यहां विशेष रूप से अनारक्षित टिकट वाले यात्रियों को रोका जाता था ताकि प्लेटफॉर्म पर एक साथ अत्यधिक भीड़ न पहुंचे. स्टेशन निदेशक के निर्देश पर वरिष्ठ अधिकारियों को भी यात्रियों की आवाजाही पर निगरानी की जिम्मेदारी दी गई थी. उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय के अनुसार, नई रंग आधारित व्यवस्था यात्रियों को सही प्रवेश द्वार तक पहुंचाने में मदद करेगी. इससे स्टेशन परिसर में अनावश्यक भीड़ कम होगी और यात्रियों की आवाजाही पहले की तुलना में अधिक व्यवस्थित हो सकेगी. रेलवे को उम्मीद है कि यह प्रयोग स्टेशन प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण दोनों के लिए कारगर साबित होगा.

दिल्ली-एनसीआर में केमिस्टों की हड़ताल का मिला-जुआ असर, मेडिकल स्टोर बंद हैं तो यहां पर आसानी से मिलेंगी दवाएं

नई दिल्ली । ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स के आह्वान पर बुधवार को दिल्ली-एनसीआर में केमिस्ट हड़ताल का मिला-जुला असर देखने को मिला।

कई स्थानीय बाजारों में मेडिकल स्टोर बंद रहे तो कहीं खुले भी मिले। जबकि अस्पताल परिसरों, सरकारी केंद्रों और बड़ी फार्मेसी चेन की दुकानें सामान्य रूप से खुली रहीं। हड़ताल ऑनलाइन दवा बिक्री और ई-फार्मेसी प्लेटफॉर्म के विरोध में बुलाई गई थी। केमिस्ट संगठनों का कहना है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भारी छूट देकर पारंपरिक मेडिकल स्टोरों के कारोबार को प्रभावित कर रहे हैं।

दिल्ली में कई बाजारों में दुकानें बंद

दिल्ली के लक्ष्मी नगर, प्रीत विहार, करोल बाग और चांदनी चौक समेत कई इलाकों में स्थानीय मेडिकल स्टोर बंद दिखाई दिए। हालांकि एम्स, सफदरजंग, आरएमएल और एलएनजेपी जैसे बड़े सरकारी अस्पतालों और निजी नर्सिंग होम के पास स्थित मेडिकल स्टोर खुले रहे, जिससे मरीजों को राहत मिली।

गाजियाबाद में आंशिक असर

गाजियाबाद के राजनगर, कविनगर, इंदिरापुरम, वैशाली और वसुंधरा में कई बड़े रिटेल मेडिकल स्टोर बंद रहे। वहीं एमएमजी जिला अस्पताल और कंबाइंड अस्पताल के सामने की दुकानें खुली रहीं।

कई कॉर्पोरेट फार्मेसी चेन ने भी सेवाएं जारी रखीं।

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कम असर

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हड़ताल का असर अपेक्षाकृत कम रहा। सेक्टर-18, सेक्टर-62 और परी चौक जैसे व्यावसायिक इलाकों में कई दुकानें खुली मिलीं। आईटी और कॉर्पोरेट हब होने के कारण यहां ऑनलाइन दवा डिलीवरी सेवाएं भी सक्रिय रहीं।

फरीदाबाद में भी अधिक स्टोर खुले रहे

फरीदाबाद के ओल्ड फरीदाबाद, एनआईटी और बल्लभगढ़ में अधिकर मेडिकल स्टोर खुले मिले। बीके अस्पताल और एनएच-3 के आसपास मेडिकल स्टोर खुले रहे।

गुरुग्राम में भी कम असर

गुरुग्राम में हड़ताल का असर सबसे कम देखने को मिला।

मेदांता, फोर्टिस और आर्टेमिस जैसे बड़े अस्पतालों की फार्मेसी सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहीं।

स्वीकृत सड़क छोड़ दूसरी सड़क निर्माण कराने का आरोप

ओएसडी के निर्देश के बाद भी नहीं शुरू हुआ स्वीकृत मार्ग का निर्माण

भटनी देवरिया।

विकासखंड भटनी के घाटी बाजार क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत रानी घाट संपर्क मार्ग से बांगलापार तक लोक निर्माण विभाग देवरिया द्वारा स्वीकृत सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग द्वारा स्वीकृत सड़क का निर्माण न कराकर दूसरी सड़क पर कार्य कराया जा रहा है। जानकारी के अनुसार उक्त सड़क का टेंडर एवं अन्य सभी प्रक्रियाएं लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्ण कर ली गई थीं।

क्षेत्रीय विधायक सभाकुंवर कुशवाहा द्वारा 12 मई 2026 को सड़क का भूमि पूजन भी किया गया था। इसके बावजूद स्वीकृत मार्ग को छोड़कर अन्य सड़क पर निर्माण कार्य शुरू करा दिया गया है। ग्रामीण अभय कुमार यादव ने इस संबंध में मुख्यमंत्री के ओएसडी से मिलकर शिकायती पत्र सौंपा था। शिकायत पर ओएसडी द्वारा लोक निर्माण विभाग देवरिया के ईई को स्वीकृत सड़क का ही निर्माण कराने का निर्देश भी दिया गया, लेकिन आरोप है कि मिलीभगत से आदेश की अनदेखी की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि जिस सड़क पर वर्तमान में कार्य कराया जा रहा है, वहां विगत वर्ष लगभग 400 मीटर इंटरलॉकिंग का निर्माण पहले ही हो चुका है। ऐसे में उसी मार्ग पर दोबारा कार्य कराना न्यायसंगत एवं उचित नहीं है। मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना हुआ है।

नई आभा से निखरेंगे गोरखपुर के मुख्य मार्ग, होगा सौंदर्यीकरण

डिवाइडर का होगा कलात्मक विकास, लगाई जाएंगी थिमेटिक प्रतिमाएं

कहीं वाद्य यंत्र, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह तो कहीं योग की मुद्राओं के तर्ज पर संवारे जाएंगे डिवाइडर

सैलानियों के मन में रच बस जाएगी विकसित गोरखपुर की छवि

गोरखपुर। स्मार्ट सिटी गोरखपुर में सड़कों को चौड़ा करने के बाद योगी सरकार उनके सौंदर्य को निखारने की पहल कर रही है। गोरखपुर के मुख्य मार्ग अब नई आभा से निखर उठेंगे। इसके लिए मुख्य मार्गों के डिवाइडर पर थिमेटिक प्रतिमाओं की स्थापना कर उनका कलात्मक विकास किया जाएगा। इस नए प्रोजेक्ट का उद्देश्य राहगीरों और सैलानियों के मन में गोरखपुर की छवि को अविस्मरणीय बनाना है। मुख्य मार्गों के डिवाइडर के कलात्मक विकास की परियोजना को पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल पर मूर्त रूप दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का प्रस्तुतिकरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष किया जा चुका है और नगर निगम बोर्ड में इस संबंध में प्रस्ताव पारित होने के बाद अब काम शुरू होने जा रहा है। एक माह में परियोजना आकार लेने लगेगी। महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव बताते हैं कि गोरखपुर के मार्गों पर बने डिवाइडर का सौंदर्य अब केवल हरियाली तक सीमित नहीं रहेगा। अब उन्हें कलात्मक और सांस्कृतिक पहचान भी मिलेगी। डिवाइडर को थिमेटिक सांस्कृतिक रूप देने के लिए कहीं राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह और वाद्य यंत्रों की आकृतियां दिखाई देंगी तो कहीं योग मुद्राओं की प्रतिमाएं आकर्षण का केंद्र बनेंगी। इसके जरिये गोरखपुर शहर को आधुनिकता के साथ भारतीय संस्कृति तथा परंपरा से जोड़ा जाएगा। महापौर का मानना है कि आने वाले समय में गोरखपुर की सड़कें केवल यातायात का माध्यम नहीं बल्कि कला, संस्कृति और आधुनिक विकास का प्रतीक बनकर लोगों को आकर्षित करेंगी। परियोजना के अंतर्गत प्रमुख चौराहों व मार्गों पर थिमेटिक प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। इन प्रतिमाओं में संगीत, योग, अध्यात्म और भारतीय जीवनशैली की झलक देखने को मिलेगी। इससे न केवल शहर की सुंदरता बढ़ेगी बल्कि बाहर से आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं के मन में विकसित और व्यवस्थित गोरखपुर की सकारात्मक छवि भी बनेगी। सड़क किनारे आकर्षक लाइटिंग पहले से है। अब डिवाइडर पर हरियाली के बीच कलात्मक संरचनाओं के माध्यम से शहर को नया रूप दिया जाएगा। नगर के प्रवेश मार्गों और प्रमुख यातायात मार्गों को विशेष रूप से चिन्हित कर उनका सौंदर्यीकरण कराया जाएगा ताकि शहर में प्रवेश करते ही लोगों को आधुनिक और स्वच्छ गोरखपुर का अनुभव हो।

पांच साल बाद महिला के शिकायत पर दर्ज हुआ छेड़खानी का मुकदमा

पटहेरवा। कुशीनगर । घटना के पांच बाद न्यायालय के आदेश पर महिला ने छेड़छाड़ व मारपीट की मुकदमा पांच व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज कराई है।जबकि न्यायालय ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश 2021 में ही दी थी। पटहेरवा के एक गांव की महिला ने न्यायालय में एक प्रकीर्णवाद दाखिल कर कही थी कि उसके पति रोजगार के सिलसिले में घर से बाहर थे।उसका पड़ोसी उस पर बदनीयती से दिखता था।जिससे वह बहुत दिनों तक नजरअंदाज किया।फिर वह उसके मोबाइल पर अश्लील मैसेज भेजना शुरू कर दिया।जब वह तंग हो गयी तो इसकी शिकायत की।जिससे नाराज होकर अचानक घर मे घुसकर मोबाइल छीनने लगा और उसके साथ छेड़खानी करना शुरू कर दी।शोर मचाने पर उसके स्वजन आये तो उसे ही मारपीट कर घायल कर दिए और घर से रुपये व गृहस्थी के सामान भी उठा ले गए।घटना 23 2021 की है।लेकिन पुलिस ने उसकी शिकायत पर कोई कार्यवाई नही की।न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य को अवलोकन के बाद पुलिस को मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया था।पुलिस ने अब आरोपित महेंद्र,साबिता,धर्मेंद्र,नयन,व दिनानाथ के विरुद्ध मुकदमा दर्ज की है।थानाध्यक्ष धीरेंद्र कुमार राय ने बताया है कि मामले की जांच की जा रही है।

सीएम के आगमन को लेकर प्रशासनिक अमला मुस्तैद, डीएम-एसपी ने खुद खींचा सुरक्षा और व्यवस्था का खाका

22 मई को जनपद पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हेलीपैड मंच और बैरिकेडिंग की तैयारियों का लिया जायजा

देवरिया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनपद में प्रस्तावित आगमन को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस महकमा पूरी तरह मुस्तैद हो गया है। तैयारियों को त्रुटिहीन और समयबद्ध ढंग से पूरा करने के लिए बुधवार को जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी और पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर. शंकर ने स्वयं मोर्चा संभाला। दोनों शीर्ष अधिकारियों ने भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अमले के साथ तहसील क्षेत्र के भीमपुर गौरा के समीप पोखरभिंडा स्थित कार्यक्रम स्थल का सघन स्थलीय निरीक्षण किया।

वीवीआईपी प्रोटोकॉल और सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए किए गए इस दौरे का उद्देश्य जमीनी स्तर पर हर एक मुकम्मल व्यवस्था को समय से पहले चाक-चौबंद करना है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने कार्यक्रम स्थल पर बनने वाले हेलीपैड की

लोकेशन, वीआईपी और आम जनता की पार्किंग व्यवस्था, रूट डायवर्जन, मंच की ऊंचाई, टेंटिंग और सुरक्षा बैरिकेडिंग का बारीकी से जायजा लिया।

जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग और संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को कड़े निर्देश दिए कि धूप और गर्मी के मौसम को देखते हुए कार्यक्रम स्थल पर बड़े पैमाने पर छाया, शुद्ध पेयजल और वीआईपी व आम जनता के लिए अलग-अलग सुचारु प्रवेश द्वारों की व्यवस्था की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्यक्रम में आने वाले जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों और आम जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। स्थल निरीक्षण के तत्काल बाद जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराने के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। जिलाधिकारी ने %चेकलिस्ट% के आधार पर प्रत्येक बिंदु की समय-सीमा तय करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के आगमन में अब बेहद कम समय बचा है, इसलिए सभी अधिकारी दफ्तरों से निकलकर फील्ड में सक्रिय रहें। उन्होंने चेतावनी दी कि तैयारियों की नियमित मॉनिटरिंग वे स्वयं करेंगे और किसी भी स्तर पर ढिलाहवाली या गुणवत्ता में कमी मिलने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध तत्काल कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर. शंकर ने भी पुलिस उपाधीक्षकों और थाना प्रभारियों को स्पष्ट खाका सौंप दिया है।

छवि खराब करने की शिकायत, कार्यवाई की मांग

पटहेरवा। कुशीनगर ।

वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व जिला पंचायत सदस्य ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया कि उनके विरोधियों द्वारा बिना किसी साक्ष्य उन पर भूमि कब्जा आदि का लांक्षन लगाकर उनकी छवि खराब की जा रही है।पुलिस को तहरीर देकर कार्यवाई की मांग की है। पटहेरवा के गांव अमवा श्रीदुबे निवासी भाजपा नेता निवासी व पूर्व जिला पंचायत सदस्य ने आरोप लगाया कि उनके गांव व पड़ोस कथित सोसल एक्टिविस्ट द्वारा लगातार उनके विरुद्ध झूठा व भ्रामक खबर चलाया जा रहा है।जिससे उनकी पार्टी,उनकी छवि को गहरा आघात पहुँचा है।आम जनता में उनके प्रति गलत संदेश जा रहा है।जिससे उनकी राजनीतिक व सामाजिक प्रतिष्ठा गिरा है।उन्होंने पुलिस को तहरीर देकर इन लोगों के विरुद्ध कार्यवाई की मांग की है।थानाध्यक्ष धीरेंद्र कुमार राय ने बताया कि घटना की जांच कर कार्यवाई की जायेगी।

आर्थिक मदद को तरस रहा है परिवार, शासन प्रशासन मौन - रामचन्द्र सिंह

कप्तानगंज(कुशीनगर)। एक तरफ तो सरकार का दावा करती है कि सभी वर्ग के लोगों को किसी खास मुसीबत में सरकार उनके साथ है मगर जनपद कुशीनगर के ग्रामसभा पिपरा खुर्द टोला मंझरिया विकास खण्ड नेबुआ नौरंगिया, तहसील, पडरौना जनपद, कुशीनगर के संजय मौर्य पुत्र सुरेश मौर्य एक निर्धन परिवार से संबंध रखते हैं वह अपने परिवार की रोजी-रोटी की व्यवस्था के लिए तमिलनाडु के एक सरिया फैक्ट्री में ठेकेदार के अधीन कार्य करते थे कुछ दिन पूर्व उनके पैर में सरिया घुस जाने की वजह से काफी चोटें आ गई थी और वह अपनी रोजी-रोटी छोड़कर अपने घर आए और इलाज के लिए गोरखपुर एम्स में गए जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें पैर का ऑपरेशन करने के लिए कहा। कहते हैं -मरता क्या नहीं करता- संजय मौर्य अपने इलाज के लिए लगभग तीन लाख रुपए का व्यवस्था जैसे तैसे करके गोरखपुर एम्स में अपना ऑपरेशन कराए और आज आर्थिक तंगी के वजह से पीड़ित है। संजय मौर्य के परिवार में उनकी चार पुत्री है जो कमशः 14, 13, 07 और 05 वर्ष की है और उनकी पत्नी की हालत भी इस समय काफी खराब है क्योंकि, उनके पेट में जो बच्चा था वह पेट में ही मर चुका था जिसका आपरेशन कराकर निकाला गया तब जाकर उनके पत्नी की जान बची। कुल मिलाकर देखा जाय तो संजय मौर्य का परिवार इस समय आर्थिक तंगी से जूझ रहा है और जिले का कोई जनप्रतिनिधी इस परिवार का खोज खबर नहीं ले रहा है। आज दिनांक 20 मई 2026 को भारतीय किसान यूनियन (जनकल्याण) के प्रदेश अध्यक्ष व भावी विधायक प्रत्याशी 329, खड्डा विधानसभा क्षेत्र 2027 को किसी के द्वारा पता चला तो पीड़ित के घर जाकर उनके परिवार से मुलाकात किए और उन्हें ढाढस बढ़ाया कि, शासन प्रशासन सहित जिले के जितने भी जनप्रनिधि है उनसे मैं अपील करके यथा संभव मदद कराने के लिए कार्य करूंगा। भारतीय किसान यूनियन जनकल्याण के प्रदेश अध्यक्ष व भावी विधायक प्रत्याशी 329, खड्डा विधानसभा क्षेत्र 2027 शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से मांग करते है कि, इस परिवार की आर्थिक मदद कराया जाए जो जनहित में होगा साथ ही शासन प्रशासन को अगवत कराना चाहते है कि, यदि जनपद कुशीनगर में कल कारखाने होते तो इस जनपद के बेरोजगार और मजदूर वर्ग के लोग अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए अन्य प्रान्तों में जाने के लिए विवश नही होते।

विभिन्न विकास परियोजनाओं का जिलाधिकारी व ब्लॉक प्रमुख ने किया लोकार्पण

कप्तानगंज(कुशीनगर)।

कप्तानगंज ब्लॉक में मंगलवार को 28 लाख 58000 के महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर और ब्लॉक प्रमुख विशाल सिंह ने मिलकर किया। जिसमे मॉडल आवास दो, राम रक्षा सिंह लाइब्रेरी 6 लाख 91,000, पशुपतिनाथ उपाध्याय मीटिंग हॉल 9 लाख 81,000 हजार तथा ब्लॉक परिसर की सीढ़ी व छत मरम्मत 9 लाख 86,000 हजार कुल 28 लाख 58000 की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने कहा कि ये परियोजनाएं स्थानीय जनता की सुविधा और विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। उन्होंने सभी परियोजनाओं के समय पर पूरा होने पर संतोष व्यक्त किया और अधिकारियों से कहा कि गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित किया जाए। ब्लॉक प्रमुख विशाल सिंह ने कहा कि विकास कार्यों के माध्यम से नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सभी परियोजनाएं पारदर्शिता

और जिम्मेदारी के साथ पूरी की जाएंगी। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी ने ब्लॉक परिसर में पौधारोपण भी किया, जिससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। जेई संतोष कुमार राय ने उपस्थित लोगों को परियोजनाओं की लागत, कार्य की समयसीमा और तकनीकी विशेषताओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन दिनेश सिंह ने किया जबकि अध्यक्षता नगर अध्यक्ष प्रतिनिधि विजय खेतन ने की। लोकार्पण कार्यक्रम में जॉइंट मजिस्ट्रेट कसया, डीसी मनरेगा राकेश कुमार, बीडीओ अमरनाथ पांडेय, उप जिलाधिकारी मोहम्मद जफर, तहसीलदार चंदन शर्मा, एपीओ अमित भार्गव, शैलेंद्र प्रताप सिंह, रंजीत प्रताप सिंह, मुकुल सिंह, ग्राम प्रधान सुभाष यादव, रंजीत कनौजिया, विजय कनौजिया, अखिलेश सिंह, गौतम सिंह सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

जिसमे मॉडल आवास दो, राम रक्षा सिंह लाइब्रेरी 6 लाख 91,000, पशुपतिनाथ उपाध्याय मीटिंग हॉल 9 लाख 81,000 हजार तथा ब्लॉक परिसर की सीढ़ी व छत मरम्मत 9 लाख 86,000 हजार कुल 28 लाख 58000 की परियोजनाओं का लोकार्पण किया।